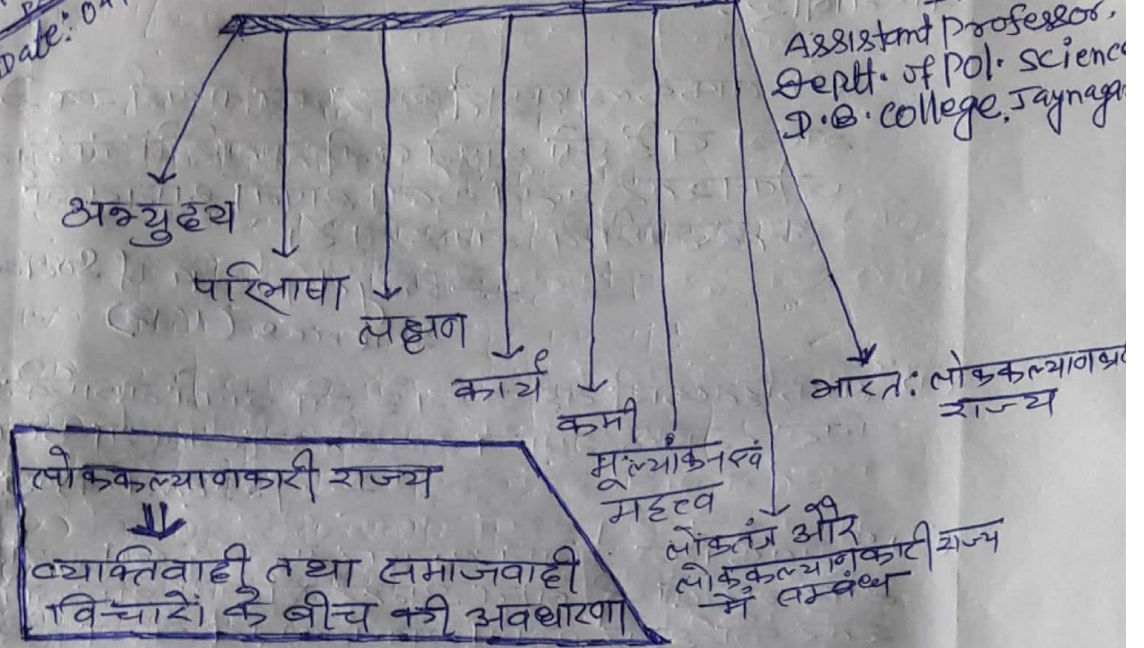


लोककल्याणकारी राज्य

By: OM KUMAR SINGH

Assistant Professor,  
Dept. of Pol. Science  
D.B. College, Jaynagar



अभ्युदय:

आधुनिक उदारवादी विद्वान् से ही 20वीं शताब्दी के प्रवाह में लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई। टी. एच. ग्रिन को इस अवधारणा का अग्रदूत माना जा सकता है।

'कल्याणकारी राज्य' शब्द का प्रयोग पहली बार आर्कबिशप टैम्पिल ने अपनी कृति 'Citizen and Churchman' में अधिनायकों के 'सत्तावादी राज्य' शब्द के विरोध में किया।

ब्रिटेन को पहला लोककल्याणकारी राज्य माना जाता है, क्योंकि वहाँ की स्टर्ली लरकर के द्वारा पाँच बड़ी बुशइयों - बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भ्रष्टाचारी तथा आश्रयाभाव के समाप्ति में राज्य की सकारात्मक भूमिका सम्बंधी कई विलियम वेवरिज की 1943ई रिपोर्ट लागू की गई। वैसे लोककल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। भारत में प्राचीन काल से रामराज्य की धारणा प्रचलित है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। महा-भारत, पाशावर की स्मृतियाँ तथा मार्कण्डेय, मनु और याज्ञवल्क्य, आदि की विचारधारा में लोककल्याण की बात स्पष्टता से देखी जा सकती है। वेदव्यास में महाभारत में कहा है कि "जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का नागी होता है।" इसी तरह श्रीधरानुदान में भी प्रचलित थी। लयो और अरलु के विचारों- इसी तरह के रहे हैं। टामस पेन, थामस जॉफरसन, कण्ट, गीन और वेथम की विचारधाराओं में राज्य का कार्य लोक कल्याण होना चाहिए, स्पष्ट होता है।

2)

परिभाषाएँ:

(i) लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है।  
— Encyclopaedia of Social Sciences (1918)

(ii) "लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है।"  
— टी. टब्ल्यू. केण्ट

(iii) "सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अन्तर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोकहितकारी राज्य के आध्यात्मिक तत्व हैं।"  
— जवाहरलाल नेहरू

(iv) "कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य आय के अधिकधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है।"  
— डॉ. अब्राहम

(v) "लोककल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उच्चानकारी और उद्योगपूर्ण है। इस राज्य का यथार्थ उद्योग नागरिक द्वारा स्वतंत्रता के उपयोग का सम्भव बनना है।"  
— न्यायमूर्ति हागसा

(vi) "कल्याणकारी राज्य ही अतिधियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियमित व्यक्तिवाद।"  
— होल्मेन

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करते हुए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। यह अपने नागरिकों के अधिक श्रेष्ठ समाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Next -

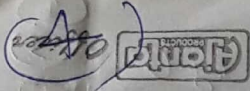
उद्देशः - लक्ष्य/किरीचतारें ,

- (i) लोककल्याण का लक्ष्य ।
- (ii) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था ।
- (iii) अधिकतम समानता की स्थापना करना ।
- (iv) राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि ।
- (v) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ।
- (vi) सभी व्यक्तियों के रोजगार ।
- (vii) न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी ।
- (viii) राजनीति व्यवस्था उचित प्रकार से करना ।
- (ix) नागरिक स्वतंत्रताएँ ।
- (x) गरीबी उन्मूलन ।
- (xi) समानता ।
- (xii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना ।

कार्य :

लोककल्याणकारी राज्य के कार्य काफी विस्तृत हैं। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- (i) आन्तरिक सुरक्षा तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना ।
- (ii) कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना ।
- (iii) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उचित प्रबंध करना ।
- (iv) जनमानस के जीवन-स्तर को उपर उठाना ।
- (v) सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना ।
- (vi) व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के सम्बंधों की व्यवस्था करना ।
- (vii) नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उचित कदम उठाना ।
- (viii) नागरिकों को आमोद-प्रमोद की सुविधाएँ उपलब्ध करना ।
- (ix) नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना ।
- (x) न्याय व्यवस्था करना ।
- (xi) उचित मुद्रा प्रबंधन ।
- (xii) कर संग्रह ।



लोककल्याणकारी राज्यों की कमियाँ :-

- (i) अत्यधिक खर्चीला ;
- (ii) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दहन ;
- (iii) नीकरशाही का अय ;
- (iv) शैक्षिक समुदाय पर आधारित ;

मूल्यांकन एवं महत्व :

वर्तमान में लोककल्याणकारी राज्यों की उपर्युक्त कमियाँ इस राज्यों की नहीं हैं, बल्कि मानवीय जीवन की हैं। इसमें सुधार लाकर उन्हें टूटकर लोककल्याणकारी राज्यों के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। व्यवहार में लोककल्याणकारी राज्यों की प्रवृत्ति को विश्व में अनेक राज्यों के द्वारा किसी-न-किसी रूप में अपना लिया गया है, जो इसके महत्व की स्वतः व्याप्ति बताती है।

लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्यों में सम्बंध :

कल्याणकारी राज्यों और लोकतंत्र में गहरा सम्बंध है। लोककल्याण की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र की मजबूती प्रदान की। विश्व के अनेक देशों ने इसे अपनाकर कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान किया है। हालाँकि वर्तमान में भी कई देश आर्थिक विषमता सहित कई संकटों से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाकर किया जा सकता है। लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्यों एक-दूसरे के पूरक हैं और वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना नितान्त ज़रूरी है।

आलः लोककल्याणकारी राज्यों :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर लोककल्याणकारी राज्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया।

By: OM KUMAR  
Singh  
Assistant Professor

संभावित प्रश्न: लोककल्याणकारी राज्यों से क्या समझते हैं। इसके लक्षणाँ एवं कार्य का वर्णन कीजिए।